**2017** आरएसटीवी के सब्सक्राइबर की संख्या 4.5 लाख थी। पिछले 29 महीनों में इसमें 888 फीसद इजाफा हुआ है। 2011 में शुरू हुए आरएसटीवी का संचालन राज्यसभा करती है।



## न्यूज गैलरी

### एयर डिफेंस कमान के गठन की तैयारी

**नई दिल्ली :** देश के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही एयर डिफेंस कमान का गठन किया जाएगा। एक दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद संभालने वाले जनरल बिपिन रावत ने अपने पहले फैसले में 30 जून तक एयर डिफेंस कमान का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। जनरल रावत ने बुधवार को ही देश के पहले सीडीएस तौर पर बागडोर संभाली थी। पदभार संभालने के बाद सीडीएस ने एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधिकारियों के साथ बैठक की और अनेक प्रकोष्ठों के प्रमुखों को तीनों सेनाओं के बीच समयबद्ध तरीके से तालमेल और सामंजस्य बढ़ाने के लिए सिफारिशें देने को कहा। एक अधिकारी ने कहा, 'सीडीएस ने निर्देश दिया है कि एयर डिफेंस कमान बनाने के प्रस्ताव को 30 जून तक तैयार किया जाए।' सीडीएस के रूप में जनरल रावत रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होंगे। वह नए गठित सैन्य मामलों के विभाग का कामकाज देखेंगे। (प्रेट्र)

### गृह मंत्रालय के दो डिवीजनों का विलय, कार्यों का आवंटन

**नई दिल्ली :** गृह मंत्रालय ने दो डिवीजनों का पुनर्गठन करते हुए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के बीच कार्यों का नए सिरे से बंटवारा किया है। आंतरिक सुरक्षा-2 डिवीजन का आंतरिक सुरक्षा-1 डिवीजन के साथ विलय हो गया है। अब इसे आंतरिक सुरक्षा (आइएस) डिवीजन के नाम से जाना जाएगा। मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र के अनुसार, 'संयुक्त सचिव (महिला सुरक्षा) को आंतरिक सुरक्षा डिवीजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अब इस पद को संयुक्त सचिव (महिला सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा) के नाम से जाना जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि अयोध्या व उससे संबंधित फैसलों को उप सचिव (राष्ट्रीय एकीकरण) द्वारा संयुक्त सचिव जम्मू-कश्मीर व लद्दाख (जेकेएल) के माध्यम से सहायक सचिव जेकेएल के समक्ष रखा जाएगा। सहायक सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) की सभी फाइलें अब सचिव (सीमा प्रबंधन) के माध्यम से भेजी जाएंगी। (एएनआइ)

### पाक में जन्मे व्यक्ति को गृह मंत्रालय ने गोवा जाने से रोका

**पणजी :** कराची में जन्मे एक आस्ट्रेलियाई नागरिक को गृह मंत्रालय ने गोवा की यात्रा की अनुमति नहीं दी। एनआरआइ मामलों के राज्य आयोग ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा क्लीयरेंस लंबित रहने के कारण यात्रा रोकी गई है। एनआरआइ मामलों के निदेशक एंथनी डिसूजा ने गुरुवार को बताया कि पाकिस्तान में जन्मे मार्को मोंटैरो (21) उन आठ छात्रों में शामिल है, जिसे आयोग द्वारा आयोजित 12वें 'नो गोवा' कार्यक्रम में भाग लेना था। डिसूजा ने कहा, 'गृह मंत्रालय ने मार्को को भारत की उसकी यात्रा के लिए सुरक्षा संबंधी अनुमति अभी नहीं दी है। मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत सचेत रहता है।' मार्को का तीन अक्टूबर 1998 को कराची में जन्म हुआ था। 'नो गोवा' कार्यक्रम का आयोजन गोवा समुदाय के वे युवा करते हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ हो और जो विदेशी नागरिक हों, लेकिन जिनके पूर्वज गोवा मूल के हों। (प्रेट्र)

### न्यायिक हिरासत में भेजे गए डीआरआइ एडीजी

**नई दिल्ली :** तीन करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में सीबीआइ ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) के वरिष्ठ अधिकारी और दो कथित बिचौलियों को गुरुवार को दिल्ली में विशेष न्यायाधीश के निवास पर पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने तीनों को 6 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआइ ने बुधवार को डीआरआइ के लुधियाना में तैनात अतिरिक्त महानिदेशक चंद्र शेखर और दो अन्य अनूप जोशी और राजेश ढांडा को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि जून 2019 में डीआरआइ ने निजी समाशोधन एजेंसी में छापेमारी की थी, जहां से एक निर्यातक से संबंधित कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे। राहत देने के लिए चंद्र शेखर के करीबी दोस्त राजेश ढांडा और बिचौलिये अनूप जोशी ने तीन करोड़ रुपये की मांग की थी। (जासं)

# केंद्र सरकार कोटा भेजेगी डॉक्टरों व विशेषज्ञों की टीम

**बच्चों की मौत का मामला** ▶ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गहलोत को पत्र लिखकर हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का दिया भरोसा

### 2019 में इस अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की मृत्यु दर हुई 20.2 फीसदी

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

कोटा में बच्चों की मौत को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर बच्चों की मौत रोकने के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बच्चों की मौत के कारणों की पड़ताल के लिए विशेषज्ञों की टीम कोटा भेज रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है और केंद्र की ओर से सभी तरह की तकनीकी व अन्य सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लिखा, 'हम हर तरह की तकनीकी व अन्य सहायता देने को तैयार हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इलाज या सिस्टम की कमियों से किसी बच्चे की जान नहीं जाए।'

राजस्थान के कोटा जिले में गुरुवार को जेके लोन अस्पताल में उपचाराधीन शिशु। प्रेट्र

हर्षवर्धन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि एम्स जोधपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शुक्रवार को कोटा पहुंच जाएगी। इस टीम में जयपुर स्थित स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रीय निदेशक भी होंगे। विशेषज्ञों की यह टीम बच्चों की मौत के असली कारण जानने का प्रयास करेगी। यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं कौन सी कमियां दूर करने से बच्चों को उचित इलाज मिल सकेगा और इसमें कितना खर्च आएगा।

वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि अस्पताल के 70 फीसद जरूरी उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। इनमें नवजात बच्चों के लिए जरूरी ऑक्सीमीटर, वार्मर्स, इनफ्यूजन पंप्स, नेबुलाइजर्स आदि शामिल हैं। यही नहीं, वहां बाल चिकित्सा विभाग में स्टाफ की भी कमी है। पिछले कुछ वर्षों में इस अस्पताल में बच्चों की मौत में बढ़ोतरी देखी गई है। दो साल पहले इस अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों में से 14.3 फीसद की मौत हो जाती थी। 2019 में यह दर बढ़कर 20.2 फीसदी हो गई। यानी 2019 में इस अस्पताल में भर्ती होने वाले हर पांचवें बच्चे की मौत हो गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2019-20 के लिए जेके लोन अस्पताल के लिए 91.7 लाख रुपये की अग्रिम सहायता जारी की जा चुकी है। मिशन के तहत कोटा जिले को 27.45 करोड़ की सहायता भेजी जा चुकी है। हर्षवर्धन ने कहा कि यदि राजस्थान को स्वास्थ्य मिशन के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की जरूरत है, तो राज्य सरकार इसके लिए प्रस्ताव भेज सकती है। केंद्र उस पर विचार करने को तैयार है।

### राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का अस्पताल न जाना खेद की बात : भाजपा

प्रथम पृष्ठ से आगे

भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि खेद की बात है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार भी उस अस्पताल का दौरा करना जरूरी नहीं समझा जहां इतने बच्चों की मौत हो गई। पुनिया ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा सांसदों से कोटा के अस्पताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदसुलूकी की। कोटा से भाजपा सांसद व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 'राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जगह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। आंकड़ेबाजी के बजाय बच्चों की मौत रोकने की कोशिश करनी चाहिए।'

**कमेटी ने अस्पताल की हालत पर उठाए थे सवाल :** दो दिन पहले राजस्थान सरकार की एक समिति ने यह पाया था कि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में बेड का अभाव है और उसके कामकाज में सुधार की जरूरत है। कमेटी ने हालांकि डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं पाई थी। तीन सदस्यीय समिति को 23 और 24 दिसंबर को दस बच्चों की मौत के बाद अस्पताल में जांच करने के लिए भेजा गया था।

**मंत्री ने गिनाए कारण :** राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा का कहना है कि बच्चों की मौत के कई कारण हैं। इनमें तेज ठंड, बच्चों का प्रीमेच्योर बर्थ (समय से पहले जन्म), जन्म के समय कम वजन या दूर अन्य अस्पतालों से रेफर होने पर जेके लोन में लाने तक बच्चे के परिजनों द्वारा सतर्कता नहीं बरतना शामिल है। डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन पाइप लाइन नहीं होना भी बच्चों की मौत का कारण है। अब तक सिलेंडरों से ऑक्सीजन पहुंचाया जाता था, जिससे इंफेक्शन का खतरा हमेशा रहता था। कुछ बच्चों में इंफेक्शन की बात भी सामने आई थी। अब ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से बच्चों की मौत की संख्या में कमी आई है।

# छह करोड़ किसानों को पीएम का नए साल में तोहफा

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

- हमने खेती को टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में देखा : मोदी
- पीएम-किसान योजना पर राजनीति करने वालों ने किसानों का नुकसान किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक समारोह में देश के छह करोड़ किसानों के खाते में 12 हजार करोड़ रुपये जमा कराकर नए साल का तोहफा दिया। इस योजना का लाभ बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों के किसानों को मिल रहा है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह की सोच ने देश के लोगों का बहुत नुकसान किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम किसान से न जुड़ पाने वाले राज्य इस साल योजना से जरूर जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक में एक समारोह में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार ने कृषि को टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में देखा है। इस सेक्टर की चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, स्वायल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया समेत कृषि क्षेत्र में किए गए सरकार के प्रयासों का ब्योरा भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान कृषि में भविष्य की जरूरतों पर है। इसके तहत ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईनाम) का विस्तार किया जा रहा है। इसी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों व उन्नतशील किसानों को पुरस्कृत किया।

कर्नाटक में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान योजना के लाभार्थी किसान को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (दाएं) व सीएम बीएस येद्दयुरप्पा (बाएं) भी मौजूद रहे। प्रेट्र

मोदी ने कहा, 'पीएम-किसान योजना के साथ राजनीति कर इसे लागू न करने वाले राज्यों ने गरीब किसानों का बहुत नुकसान किया है। इस तरह की राजनीति करने से किसान कभी मजबूत नहीं होगा।' दरअसल, योजना की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी। बंगाल को छोड़ लगभग सभी राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। बंगाल के 70 लाख किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस योजना का मुखर विरोध करती रही हैं। राज्य के 45 हजार किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लिया है, लेकिन राज्य सरकार की सहमति के बगैर केंद्र सरकार के लिए इसे लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है।

2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ कार्यक्रम के दौरान तटीय मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड और गहरे समुद्र में मछली मारने वाली नौकाएं व ट्रांसपोडर्स दिए गए। अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृषि सेक्टर की महत्ता बताते हुए मोदी ने कहा कि इसके लिए नकदी फसल और निर्यात आधारित खेती पर जोर दिया जा रहा है। कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके विस्तार की जरूरत है, जिसमें पौष्टिक अनाज, बागवानी और जैविक कृषि को भी शामिल किया जाना चाहिए।

### शिवकुमार स्वामीजी को दी श्रद्धांजलि

प्रथम पृष्ठ से आगे

सभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंगायत समुदाय के प्रतिष्ठित सिद्धगंगा मठ के शिवकुमार स्वामीजी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वामीजी के काम सभी को प्रेरित करते रहेंगे। बेंगलुरु पहुंचने के बाद मोदी सीधे मठ पर पहुंचे। उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी उपस्थित रहे। समाधि पर श्रद्धांजलि के बाद मोदी ने मठ के परिसर में बेल का पौधा लगाया और स्वामीजी को समर्पित संग्रहालय की आधारशिला रखी। स्वामीजी को उनके भक्त ईश्वर का अवतार मानते थे। पिछले साल जनवरी में 111 साल की उम्र में उन्होंने शरीर त्यागा था।

# लोकपाल को बहुत जल्द ही मिल जाएगा स्थायी पता

- अभी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल 'द अशोक' में चल रहा है कार्यालय
- हर महीने 50 लाख रुपये आता है इस पर किराया

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वोच्च संस्था लोकपाल का कार्यालय दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल 'द अशोक' में चल रहा है। इसका किराया 50 लाख रुपये प्रति माह है। लेकिन इसी महीने यह कार्यालय लोकपाल की अपनी स्थायी इमारत में स्थानांतरित हो जाएगा।

कार्मिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उक्त जानकारी दी है। सूचना के अधिकार के तहत दायर आवेदन के जवाब में लोकपाल ने वर्तमान कार्यालय के बारे में बताया, 'कुल मासिक किराया करीब 50 लाख रुपये है और 22 मार्च, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक किराये के रूप में 3,85,09,354 रुपये का भुगतान किया गया है।' जवाब के मुताबिक, लोकपाल कार्यालय के लिए पूर्व इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन की इमारत में जगह आवंटित की गई है। लेकिन जवाब में नए कार्यालय के स्थान के बारे में विवरण नहीं दिया गया है।

इस बीच, सरकार लोकपाल में शिकायतें दायर करने के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप देने पर भी काम कर रही है। मानकों के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में ही लोकपाल के समक्ष शिकायत दाखिल की जा सकती है। अधिकारियों ने पिछले दिनों बताया, 'कानून मंत्रालय से हमें जरूरी जानकारियां मिल गई हैं। मंत्रालय में ही कुछ विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द ही प्रारूप सार्वजनिक कर दिया जाएगा।' फिलहाल लोकपाल सभी शिकायतों की जांच कर रहे हैं, भले ही वे किसी भी प्रारूप में प्राप्त हुई हों। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबकि, 30 सितंबर, 2019 तक कुल 1,065 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 1,000 का निपटारा कर दिया गया है।

मालूम हो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च, 2019 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के चैयरपर्सन के रूप में शपथ दिलाई थी। जबकि लोकपाल के आठ सदस्यों को जस्टिस घोष ने 27 मार्च, 2019 को शपथ ग्रहण कराई थी।

# चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने प्रो. सुरेश चंद्र शर्मा

- एमसीआइ संचालन मंडल के महासचिव राकेश कुमार वत्स बने आयोग के सचिव
- दिल्ली एम्स के नाक, कान व गला विभाग के प्रोफेसर हैं शर्मा

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नाक, कान व गला विभाग के प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को गुरुवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एनएमसी नया चिकित्सा शिक्षा नियामक है जो भ्रष्टाचार के आरोपों वाली भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) की जगह लेगा।

कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रो. शर्मा की नियुक्ति को तीन साल या उनकी आयु 70 साल की होने तक के लिए स्वीकृति दी है। एमसीआइ संचालन मंडल के महासचिव राकेश कुमार वत्स को इसी अवधि के लिए आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आठ अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) कानून-2019 को मंजूरी प्रदान की थी।

आयोग गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए प्रणाली उपलब्ध कराएगा और देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता तथा अन्य चीजें सुनिश्चित करेगा। नया कानून चिकित्सा शिक्षा, पेशे और संस्थानों से जुड़े सभी पहलुओं के विकास और नियमन के लिए एमसीआइ की जगह एनएमसी की स्थापना की बात कहता है। राष्ट्रपति ने 2018 में एमसीआइ को भंग कर दिया था और इसके कार्यों को अंजाम देने के लिए एक संचालन मंडल नियुक्त किया था। एनएमसी के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 72 आवेदन मिले थे।

कानून के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। एमसीआइ के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों और मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने से जुड़े मामलों की अपारदर्शी जांच के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मई 2016 में सरकार को नया कानून आने तक एमसीआइ के सभी संवैधानिक कार्यों को देखने के लिए एक समिति की स्थापना करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि एमसीआइ पर तुरंत मान्यता देने और देशभर में मेडिकल कॉलेजों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान करने में रिश्वत लेने के व्यापक आरोप लगते रहे हैं।

### यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी के सब्सक्राइबर की संख्या 40 लाख पार

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी (आरएसटीवी) के सब्सक्राइबरों की संख्या 40 लाख से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही वह यूट्यूब पर देश के टॉप-10 चैनलों में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि पर उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने गुरुवार को आरएसटीवी व उसके स्टाफ को बधाई दी है। अधिकारियों ने बताया कि यूट्यूब पर सब्सक्राइबर के मामले में कई अग्रणी न्यूज चैनल भी आरएसटीवी से पीछे रह गए हैं।

उपराष्ट्रपति नायडू ने एक साथ लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, 'अगस्त 2017 में आरएसटीवी के सब्सक्राइबर की संख्या 4.5 लाख थी। पिछले 29 महीनों में इसमें 888 फीसद इजाफा हुआ है।' उन्होंने कहा, 'यह बताता है कि चैनल सूचना और शिक्षाप्रद प्लेटफॉर्म के रूप में स्थान बना रहा है। यह सही सामग्री और रोचक प्रस्तुति के प्रति लोगों की भूख को भी दर्शाता है।' वर्ष 2011 में शुरू हुए आरएसटीवी का संचालन राज्यसभा करती है।

उल्लेखनीय है कि नायडू ने लोकसभा (एलएस) टीवी और आरएसटीवी के विलय के लिए छह सदस्यी कमेटी का गठन किया है। विलय का उद्देश्य संसद की कार्यवाही की कवरेज में होने वाले खर्च को कम करना है।

# अभी ब्रिटेन की जेल में ही रहेगा भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी, अगली सुनवाई 30 को

- 14 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपित है भगोड़ा हीरा कारोबारी
- ब्रिटेन की अदालत में 11 मई से शुरू होगी प्रत्यर्पण संबंधी सुनवाई

**लंदन, प्रेट्र :** करीब 14,000 करोड़ रुपये (करीब दो अरब डॉलर) के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले और मनी लांड्रिंग का आरोपित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में ही रहेगा। ब्रिटेन की अदालत ने गुरुवार को नियमित सुनवाई के दौरान उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 जनवरी तय कर दी है।

नीरव मोदी को 28 दिनों पर होने वाली नियमित सुनवाई के लिए लंदन के वैंड्सवर्थ जेल से वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में लाया गया। उसके प्रत्यर्पण से संबंधी सुनवाई 11 मई से शुरू होने वाली है, जो पांच दिनों तक चल सकती है। डिप्टी चीफ मजिस्ट्रेट टैन इकरम गुरुवार को इस मामले में जज की भूमिका में थे। उन्होंने नीरव मोदी से पूछा कि क्या वह किसी अन्य मुद्दे पर कुछ कहना चाहता है। नीरव मोदी ने जज के सवाल का जवाब 'नहीं' में दिया।

उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी ने गत वर्ष नवंबर में घर में नजरबंदी की गारंटी देते हुए जमानत के लिए नए सिरे से याचिका दाखिल की थी। हालांकि, चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने गवाहों को प्रभावित करने तथा मई 2020 में शुरू होने वाली सुनवाई में पेशी से भागने की आशंका जताते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

नीरव मोदी फाइल फोटो

नीरव मोदी को गत वर्ष 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। प्रत्यर्पण की कार्यवाही में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटेन की क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा था कि किसी भी उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील की कोई गुंजाइश नहीं बची है। कारण है कि ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने पहले ही नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लगातार सुनवाई के दौरान ब्रिटेन के कोर्ट को बताया गया है कि नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपित है।

### नीरव-मेहुल के जल्द प्रत्यर्पण के लिए भारत ने झोंके सभी संसाधन

**नई दिल्ली, एएनआइ :** विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों नीरव मोदी व मेहुल चोकसी के जल्द प्रत्यर्पण के लिए सरकार ने सभी संसाधन झोंक दिए हैं। साथ ही कहा कि वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए भारत और जापान कूटनीतिक माध्यमों के जरिये संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'नीरव मोदी के मामले की सुनवाई लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में हो रही है। हम नीरव मोदी के जल्द प्रत्यर्पण के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।' मेहुल चोकसी के मामले पर रवीश कुमार ने कहा, हमने एंटीगुआ और बरबुडा की सरकारों से कानूनी प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। भारत-जापान शिखर सम्मेलन के बारे में रवीश कुमार ने कहा, 'हम कूटनीतिक माध्यमों से जापानी पक्ष के साथ संपर्क में हैं। उम्मीद है कि जल्द हम तारीखों को अंतिम रूप दे सकेंगे।' जापानी प्रधानमंत्री एबी शिंजो व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिसंबर के मध्य में गुवाहाटी में होने वाला वार्षिक शिखर सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के चलते टाल दिया गया था।

## विवाद

एचआरडी सूत्र ने बताया कि अभी नहीं मिला है कोई इस्तीफा, राष्ट्रपति भवन सूत्र का कहना है कि हांगलू को हटाने की मंत्रालय की सिफारिश को राष्ट्रपति भवन पहले दो बार कर चुका है खारिज

# इलाहाबाद विवि के कुलपति के इस्तीफे की मंजूरी पर रहस्य

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू के इस्तीफे के बाद अब सभी की निगाहें राष्ट्रपति भवन पर टिकी हैं। वहां से इस्तीफा मंजूर किया जाना है। वैसे यह मसला थोड़ा रहस्यमय हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) के सूत्रों का कहना है कि कुलपति का इस्तीफा राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के सूत्र ने इस्तीफा मिलने से इन्कार किया है।

इस बीच, विश्वविद्यालय के कुलपति रतन लाल हांगलू के समर्थन में विश्वविद्यालय के कई प्रशासनिक आला अधिकारियों ने इस्तीफा सौंपकर पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश की है। जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल हांगलू के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है, उससे साफ है कि कुलपति के इस्तीफे को वापस करना बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि, यहां यह बताना जरूरी है कि इससे पहले प्रोफेसर हांगलू को हटाने व उसके खिलाफ जांच कराने की अनुमति देने वाले एचआरडी के दो प्रस्तावों को राष्ट्रपति भवन वापस कर चुका है।

राष्ट्रपति भवन ने गहन जांच करने की बात कही थी। हालांकि, प्रोफेसर रतन लाल हांगलू को लेकर विवाद उनकी नियुक्ति के बाद से ही शुरू हो गया था। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, गलत तरीके से नियुक्ति करने और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे थे। महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले की जांच फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग के पास है। पिछले दिनों आयोग ने उन्हें इस मामले में तलब भी किया था।

इस बीच, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) में इस पूरे मामले को लेकर मंत्री और अफसरों के बीच गुरुवार को कई दौर की बैठकें हुईं। सूत्रों के अनुसार, रतन लाल हांगलू के इस्तीफे को राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजने के बाद मंत्रालय ने उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया है। साथ ही कुलपति से जुड़ी शिकायतों का ब्योरा भी राष्ट्रपति को भेजा है।

हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति भवन से इसकी मांग की गई थी, या फिर इसे इस्तीफे के पक्ष को मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि हांगलू के खिलाफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी उच्च स्तरीय जांच कराई थी, जिसमें उन पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और गलत तरीके से नियुक्ति देने जैसे मामलों की पुष्टि भी हुई थी।

### ...यूं ही नहीं सौंपा हांगलू ने इस्तीफा

रतन लाल हांगलू फाइल

हांगलू खुद पर लग रहे आरोपों से पिछले चार वर्षों से बचते चले आ रहे हैं। ऐसे में यह तो साफ है कि उन्होंने यूं ही इस्तीफा नहीं दिया होगा। बल्कि इसके पीछे चौतरफा घिर जाना था। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्रीय नेतृत्व का बढ़ता दबाव था। बुधवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के बाद कवायद तेज हुई। जिसके बाद हांगलू को साफ संदेश दे दिया गया। ऐसे में हांगलू ने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा और बुधवार देर शाम अपना इस्तीफा एचआरडी मंत्रालय को भेज दिया। दबाव का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है, कि हांगलू को नए साल के पहले दिन ही इस्तीफा देना पड़ा। सूत्रों की मानें तो एचआरडी मंत्रालय पर इस्तीफे को रातों-रात राष्ट्रपति भवन भेजने का दवाब बनाया गया। जिसके बाद इसे तुरंत ही मंत्री की सिफारिश के साथ राष्ट्रपति भवन को भेजा गया।

## कह के रहेंगे

माधव जोशी